

कोरोना प्रकरण बहुत कम हो गए हैं, परन्तु सतर्कता में बिल्कुल कमी न हो : मुख्यमंत्री

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत कम हो गया है। प्रदेश के 50 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से नीचे आ गई है और प्रतिदिन नए प्रकरण 400 से नीचे आ गए हैं। रिकवरी रेट 98.2ब हो गई है।

प्रदेश का कोरोना संक्रमण की दृष्टि से देश में 23 वां स्थान है। फिर भी, हमें सतर्कता में थोड़ी भी कमी नहीं करनी है। हर व्यक्ति मास्क लगाए, परस्पर दूरी रखे और अन्य सभी सावधानियाँ बरते। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक कोरोना मरीज को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए और कोई भी मरीज छुपा न रहे यह सुनिश्चित किया जाए। एक-दो प्रकरण होने पर भी माइक्रो



कंटेनमेन्ट क्षेत्र बनाएँ, जिससे संक्रमण फैले नहीं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये बिस्तर बढ़ाने, ऑक्सीजन पाइप लाइन डालने और ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने आदि का कार्य चल रहा है। प्रभारी मंत्री अपने

जिलों में इन कार्यों का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि उत्तम गुणवत्ता का काम समय पर हो।मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। वीसी में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास

सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस,अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे। प्रदेश में कोरोना के 397 नए प्रकरण आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या पाँच हजार 447 है और 1240 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.7

प्रतिशत और आज की पॉजिटिविटी दर 0.5ब है। एक दिन में 79 हजार 261 टेस्ट किए गए हैं।

अब प्रदेश के 3 जिलों इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 10 से अधिक नए प्रकरण आए हैं। वहीं 11जिलों में 5 से अधिक नए प्रकरण हैं। इंदौर में 117, भोपाल में 97, जबलपुर में 34, बैतूल में 8, ग्वालियर में 8, हरदा में 7,खरगोन में 7, रतलाम में 7, रायसेन में 6 और राजगढ़ में 6 नए प्रकरण आए हैं। प्रदेश के दो जिलों इंदौर और भोपाल में एक प्रतिशत से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर है। इंदौर में 1.2 प्रतिशत और भोपाल में 1.8ब साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी दर है। शेष 50 जिलों में एक प्रतिशत से कम पॉजिटिविटी दर है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताएँ स्मार्ट क्लासेस बनाएँ : चौहान

भोपाल(काप्र)।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मध्यप्रदेश शासन की प्राथमिकताएँ हैं।दोनों ही क्षेत्रों में प्रदेश में व्यापक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के विस्तार के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस बनाएँ, जिससे विद्यार्थी वचुअल माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज शासकीय विक्रम महाविद्यालय खारचौद में 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत के उन्नयन कार्य का वचुअल शिलान्यास किया। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित जनों से चर्चा

भी की। खारचौद से वीसी के माध्यम से केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया शामिल हुए। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में छोटे स्थानों पर भी स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी। गाँव, कस्बों और छोटे शहरों सभी में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खारचौद में एक करोड़ 32 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है। एक वर्ष में इसका कार्य पूर्ण होगा। खारचौद में 20 लाख रुपये की लागत से नीलकंठेश्वर महादेव

मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। उन्जैन में चिकित्सा महाविद्यालय का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा। केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गेहलोत ने खारचौद से वचुअली संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश में विकास के पर्याय हैं। प्रदेश में तेज गति से विकास हो रहा है। मध्यप्रदेश सरकार के कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के कार्य अत्यंत सराहनीय हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उच्च शिक्षा विभाग का बजट दोगुना कर दिया है। प्रदेश के हर शासकीय महाविद्यालय, जिनके पास भूमि उपलब्ध है, का भवन निर्माण

भोपाल (हिन्प्र)।

योग और ध्यान पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संत महाविद्यालय में किया गया। शिक्षा विभाग ने कोरोना के साथ भी, कोरोना के बाद भी योग की महत्त्वता बताने के लिए कार्यशाला आयोजित की थी।

कार्यशाला की शुरूआत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. खलिमा पारवानी ने विषय रखने के साथ हुई। पारवानी ने कहा कि यह कार्यशाला छात्राओं के लिए शिक्षा के साथ आज के वर्तमान समय में अति आवश्यक है, इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सकारात्मकता और प्रतिरोधक क्षमता को संदेव बनाकर रख सकता है। विषय विशेषज्ञ नीलेश

विश्वकर्मा योग निरोग कार्यक्रम प्रमुख प्रशिक्षक रहे, जिन्होंने योग एवं ध्यान के विषय में बताते हुए कहा कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या को सही करके अपने मन को एकाग्र कर ध्यान का पूरा लाभ लिया जा सकता है। योग अभ्यास करने से व्यक्ति की जीवन शैली, योगासन, प्राणायाम को प्रभावी ढंग से बताते हुए आज के समय में कोविड-19 जैसी बीमारी के भय को दूर करते हुए मन को संतुलित करने व इच्छा शक्ति में वृद्धि करना बताया, जिससे शरीर की ऊर्जा क्षीण नहीं होगी। कार्यशाला के सहभागियों ने अपने प्रश्नों के उत्तर में मोटापा, अस्थमा गर्दन दर्द, कफ, वात, पित्त जैसी समस्याओं के समाधान जाने, इसके साथ ही महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सूर्य नमस्कार भी किया।

कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज शुक्ला का अनोखा प्रदर्शन

लड़की की शादी में पहुंचे, गिफ्ट में दी तेल की केन

भोपाल(काप्र)।

पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ तकरीबन हर रोज खाद्य तेल और खान-पान की दूसरी सभी चीजों के दामों ने आम आदमी की कमरतोड़ दी है। महंगाई की मार से दबे जा रहे आम आदमी की चिंता न तो केन्द्र की मोदी सरकार को है और न ही राज्य की शिवराज सरकार को।

ऐसे में बढ़ती महंगाई के विरोध में म. प्र. कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज शुक्ला ने गुरुवार को अंतोखा प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। करोंद इलाके में वाई नंबर 79 के रिंग गार्डन निवासी श्री जवाब सोलंकी की बेटी अविष्णा सोलंकी की शादी आज हो रही है। लड़की के पिता ने म. प्र. कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज शुक्ला को निमंत्रण भेजा था। शुक्ला आज इस विवाह समारोह में शामिल हुए और बिटिया को 15 लीटर तेल की केन भेंट स्वरूप दी। शुक्ला ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई कम करने की बजाए कह रहे हैं कि यही सबसे अच्छा गिफ्ट है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज देश के



गरीबों को इस दयनीय स्थिति में ला दिया है कि उनका दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई के कारण गरीब परिवारों में शादी-ब्याह की खुशियां गायब सी हो गई हैं। परिजन जैसे-तैसे अपने बच्चों के हाथ पीले कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने आका को खुश करने की खातिर, महंगाई के मुद्दे पर शिवराज मामा भी इस समय मैदान से गायब हैं। उन्हें अपनी भांजियों पर न प्रेम आ रहा है न दया। शुक्ला ने कहा कि ऐसा ही मौन क्षेत्रीय विधायक ने साध रखा है जो गरीब भांजियों और महिलाओं से हाथ भर-भर कर राखी बंधवाकर मंत्री तो बन गए लेकिन अपना उल्लू सीधा होने के बाद गरीबों के घर में झांक कर भी

नहीं देख रहे, कि महंगाई के कारण उनका जीना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कमरतोड़ महंगाई के हालातों में भारतीय जनता पार्टी नेता जनता के सामने अपना मुंह छिपा रहे हैं। सिवाय कांग्रेस को कोसने के, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। अंत्योदय की बात करते-करते भाजपा सरकारों ने आखिरी पंक्ति के व्यक्ति का जीना भी मुश्किल कर दिया है। शुक्ला ने बिटिया को आशीर्वाद दिया और उसके परिजनों को भरोसा दिलाया कि वे हर परिस्थिति में परिवार के साथ हैं। पूरे उत्साह और खुशी के साथ बेटी का ब्याह करें। इस अवसर पर मनोज ठाकुर, आनंद विश्वकर्मा, श्याम पटेल, सुमित सेन, नेमीचंद विश्वकर्मा, मनीष शर्मा, आकाश ठाकुर आदि उपस्थित थे।

ऑल इंडिया मलयाली एसो की ऑनलाइन आम सभा



भोपाल (हिन्प्र)। अखिल भारतीय मलयाली संघ मध्यप्रदेश इकाई ने वार्षिक आम बैठक ऑनलाइनआयोजित की, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव पी.एन.श्रीकुमार व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.एस.पिल्लई और चुनाव पर्यवेक्षक सुरेश कुमार नायर शामिल हुए। बैठक में क्षेत्र के अधिकांश सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में पिछले तीन वर्षों में एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मूल्यांकन किया। समाज कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक सहायता पहुंचाने में सक्षम रहा और इसकी सभी सदस्यों ने सराहना की। एसोसिएशन मध्यप्रदेश शाखा सचिव आर.एस.पिल्लई ने कार्य

रिपोर्ट प्रस्तुत की और जेली इलनूर वित्त सचिव ने राजस्व और व्यय के आंकड़े प्रस्तुत किये । इलेक्शन सर्विसम्मति से सम्पन्न हुआ, जिसमें सी. अशोकन अध्यक्ष, आर.रत्नाकरन उपाध्यक्ष, जैम्स वर्गीस-उपाध्यक्ष, एम.के.रविन्द्रन, चैयरमेन, श्रीरत्नाकरन-वाइस चेयरमेन, सतीन कुमार वाईस वेयरमेन, जोसफ थॉमस मुख्य सलाहकार, अनिल नायर सचिव, जेली इलनूर फायनंससेक्रेट्री, इन्दुराज सहसचिव, बाई जूजॉर्ज सहसचिव, दिनेश पी सहसचिव, आर.एस.पिल्लई एन.जी.सी. सदस्य, एडवोकेट जेली कुरियन,एवं वैष्णवी हरीश को युव संयोजक बनाया गया ।

संतनगर में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

भोपाल (हिन्प्र)।

देशभर में पेट्रोल- डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि के खिलाफ संतनगर में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने संतनगर पेट्रोल पंप एवं आकाश गार्डन के पास स्थित पेट्रोल पंप पर सांकेतिक विरोध किया।

आपको बता दे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पेट्रोल डीजल मूल्यवृद्धि के खिलाफ कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए संतनगर में ब्लॉक अध्यक्ष नानक चंदनानी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष



अरुण श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जनों ने पेट्रोल पंप पर महंगाई के विरोध में तख्तियां हाथ में लेकर विरोध जताया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद अशोक मारण, राम

महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तरफ कोरोना के कारण आम आदमी संकट में है तो दूसरी तरफ आए दिन बढ़ रही महंगाई ने परेशान कर रखा है। चंदनानी ने कहा की मोदी सरकार के आने के बाद पेट्रोल पर 22 रुपए और डीजल पर 28 रुपए एक्साइज इयूटी बढ़ाई गई है, अगर केन्द्र सरकार केवल एक्साइज इयूटी कम कर दें और राज्य सरकार वैट तो पेट्रोल और डीजल कम से कम 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। प्रदर्शन में प्रवक्ता विनोद राय, आत्माराम सूर्यवंशी, सुरेश सिंगरोली, हेमंत मारण, गगन भार्गव, कैलाश मेहर शामिल रहे।

केंद्र और उत्तर ...

नेताओं ने इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों, विधायकों और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों से अलग-अलग मुलाकात की थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली पहुंचने और उनकी, पार्टी के शीर्ष नेताओं से इन मुलाकातों के दौर को बीजेपी की, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। योगी की दिल्ली यात्रा से ठीक एक दिन पतरले पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामा है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य ए. के. शर्मा भी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और पार्टी के नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी का विश्वस्त माना जाता है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राज्य के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार और राजनीतिक हलके से ताल्लुक रखने वाले जितिन प्रसाद को और शर्मा को इस संभावित विस्तार में शामिल किया जाएगा।

आया मानसून...

दस्तक दे दी है। गुरुवार से ही जिले में अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश हो रही। बारिश से पहाड़ी इलाकों में नदी-नाले उफान पर आ रहे। मौसम विभाग की मानें तो समय से सात दिन पहले ही इस बार मध्यप्रदेश में सक्रिय हो गया। दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तरी सीमा व सूरत, नंदुरबार, रायसेन, दमोह, उपरिया, पंडु रोड, बोलांगीर, पुरी से होकर गुजर रही है। यही कारण है कि एक जून से लेकर शुक्रवार सुबह तक पूर्वी मध्यप्रदेश में करीब दो इंच और पश्चिम मध्यप्रदेश में करीब सवा इंच बारिश हो चुकी थी। मौसम विभाग ने होशंगाबाद, जबलपुर और सागर संभाग के अधिकांश जिलों, रीवा, शहडोल संभागों के अनेक स्थानों और इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बौछरें पड़ने की संभावना बताई है। प्रदेश के अनूपपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल और देवास जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और गिरने का यलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि रीवा, इंदौर, ग्वालियर, एवं चंबल संभागों के जिलों में, शहडोल, उमरिया, छिंडोरी, कटनी, जबलपुर, राय, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, हरदा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अगर नीचम और मंदसौर जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और 40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

सुको ने केंद्र से ...

कोर्ट ने 10 दिन मामले को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता

की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील एस बी उपाध्याय ने डेथ सर्टिफिकेट में मृत्यु की सही वजह दर्ज न करने से मुआवजा पाने में दिक्कत की दलील दी। केंद्र के वकील ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस पहलू को भी देखा जा रहा है। इसका भी समाधान निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है। पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था। इस साल ऐसा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अस्पताल से मृतकों को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। न उनका पोस्टमॉर्टम होता है, न डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि मृत्यु का कारण कोरोना था। ऐसे में अगर मुआवजे की योजना शुरू भी होती है तो लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे।

बैंक लोन की ...

न वसूला जाए। जस्टिस अशोक भूषण और एम आर शाह की बेंच ने कहा कि पिछले साल सरकार ने नीति घोषित की थी। इसके बाद कुछ याचिकाकर्ता उसके विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे। तब कोर्ट ने मामले के कुछ पहलुओं को देखा था। वित्तीय मामलों पर नीति बनाना सरकार का अधिकार है। कोर्ट इस पर सीधे कोई आदेश नहीं देगा। कोर्ट ने आगे कहा, हम वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं। सरकार को बैंकसीनेशन पर खर्च करना है। प्रवासी मजदूरों समेत कई वर्ग हैं, जिन पर खर्च करना है। बेहतर हो सरकार को ही इस मसले पर फैसला लेने दिया जाए।इसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर कोर्ट मोरेटोरियम पर कोई आदेश नहीं देना चाहता तो कम से कम यह कह दे कि बैंक लोन न चुकाने पर किसी संपत्ति की नीलामी न करें। जजों ने इससे भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हर मामले के तथ्य अलग होते हैं। इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता कि बैंक कर्ज न चुकाने वाले किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई न करें। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह सरकार को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांग रख सकता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो ऐसा कर सकता है।

चीन भारत का...

स्वस्थ एफडीआई प्रवाह की जरूरत है। अप्रैल 2020 से, भारत को चीन से लगभग 1।63 बिलियन डॉलर के 120 से अधिक एफडीआई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इंडिया ब्रीफिंग के अनुसार, इनमें से अधिकतर निवेश ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए हैं। उन्होंने यह भी नोट किया कि प्रचार के बावजूद भी हालांकि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। नई दिल्ली में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तविक अनुपात केवल 2।43 बिलियन डॉलर-कुल प्रवाह का 0।51

प्रतिशत है। सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंड, जापान, यूएस, अमेरिका उन देशों की सूची में शामिल हैं जहां से भारत को एफडीआई का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है। हालांकि, भारत की भी सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि चीन स्टार्टअप सहित भारतीय कंपनियों में अपने निवेश को तेजी से बढ़ा रहा है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने इंडिया नैरेटिव बताया कि, ऐसे फैसलों में बहुत सारे बदलाव शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्हें जल्दबाजी में संभाला जा सकता है। अधिकारियों को देश के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने होंगे। पिछले साल, सरकार ने गलवान घाटी की घटना से पहले ही अपने पड़ोसी देशों द्वारा अधिग्रहण या अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए अपनी एफडीआई नीति में संशोधन किया था। इस कदम का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को कोविड 19 महामारी के कारण गिरते मूल्यांकन के बीच शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण से बचाना था।

भारत-बांग्लादेश...

नागरिक कार्यरत हैं। इस चीनी घुसपैठिए की तलाशी लेने पर उसके पास से चीनी पासपोर्ट, एक एप्पल लैपटॉप, 02 आईफोन मोबाइल, 01 बांग्लादेशी सिम, 01 भारतीय सिम, 02 चाइनीज सिम, 2 पेनड्राइव, 03 बैटरी, दो स्मॉल टॉर्च, 05 मनी ट्रांज़ैक्शन मशीन, 02 एटीएम कार्ड, अमेरिकी डॉलर, बांग्लादेशी टका और भारतीय मुद्रा बरामद हुई। चीनी जासूस हान जुनवई भारत-बांग्लादेश सीमा पर मालुदा जिले की सुल्तानपुर बीओपी के करीब एक चोर रास्ते से पश्चिम बंगाल में दाखिल होना चाहता था, लेकिन वहां तैनात बीएसएफ के जवानों ने उसे धर-दबोचा। हालांकि, इसने भागने की कोशिश भी की थी। पृष्ठताछ में इसने बताया कि यह पहली बार साल 2010 में हैदराबाद आया था। वहीं वर्ष 2019 के बाद तीन बार दिल्ली-गुरुग्राम आ चुका है। इसका मौजूदा पासपोर्ट चीन के हुबई प्रांत का है, जो इसी साल यानी जनवरी 2021 में इश्यू हुआ।

घर में आकर...

हुई थी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी दो जून को मुकुल रॉय की बीमार पत्नी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद ही इस बात की अटकलें तेज हो गयीं कि राजनीतिक समीकरण में बदलाव आ सकता है। रॉय बीजेपी में आने से पहले तृणमूल कांग्रेस में महासचिव थे। हाल ही में अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, मुकुल (रॉय) हमारे पुराने सदस्य हैं और वह अब वापस आ गए हैं। वह भाजपा में अच्छी स्थिति में नहीं थे क्योंकि भगवा पार्टी ने एंजेंसियों के माध्यम से उन पर दबाव बनाया था, परिणामस्वरूप वह मानसिक तौर पर शांत नहीं थे। मैं देख रही हूं कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, क्योंकि कोई भाजपा में नहीं रह सकता।